

राजस्थान-सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
कमरा नम्बर 8320, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक-एफ 61(177)SSAAT/मैन विद मशीन / 2024-25 / 08153

दिनांक : ई-हस्ताक्षरित

निविदा संख्या 01 / 2025-26

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर के कार्य संचालन हेतु 06 मैन विद मशीन जाब बेसिस पर उपलब्ध/आपूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक पंजीकृत व मान्यता प्राप्त संवेदकों/सेवा प्रदाताओं से दो लिफाफा पद्धति में निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	मैन विद मशीन की अनुमानित संख्या	अनुमानित मूल्य	बिड प्रतिभूति राशि (2%)	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	06 मैन विद मशीन श्रम विभाग की निर्धारित दरो पर	रु. 9,80,000 / -	रु. 19600 / -	रु. 500 / -

निविदा प्रपत्र विभाग के कार्यालय में दिनांक 29.09.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदा शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है या राज्य लोक उपापन पोर्टल की website <https://Sppp.rajasthan.gov.in> व <https://socialaudit.rajasthan.gov.in> से देखा व डाउन लोड किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 29.09.2025 को सांय 4.00 बजे खोली जायेगी।

निदेशक
(SSAAT)

क्रमांक-एफ 61(177)SSAAT/मैन विद मशीन / 2024-25 / 08153

दिनांक : ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को संबंधित बिड को वेबसाईट एवं उचित माध्यम पर अपलोड करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक
(SSAAT)



बोली (Bid) का विवरण

बोली (Bid) की विषय वस्तु	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी शासन सचिवालय, जयपुर में 06 मैन विद मशीन की सेवाओं के उपापन हेतु बोली (Bid) आमंत्रण
बोली (Bid) जिसे सम्बोधित होगी	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर
बोली (Bid) का संदर्भ	NIB No.01/SSAAT/MWM/2025
बोली (Bid) अनुमानित राशि	रुपये 9.80 / – लाख वार्षिक
बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क	रुपये 500 / – का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट “निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के नाम से देय।
बोली (Bid) प्रतिभूति राशि	रुपये 19600 / – का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट “निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के नाम से देय।
बोली (Bid) आमंत्रण का विवरण व बोली प्रपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया व समय	बिड Document वेबसाइट https://Sppp.rajasthan.gov.in व https://socialaudit.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
बोली (Bid) प्रस्तुत करने का अन्तिम समय	बोली(Bid) मय बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क व बोली (Bid) प्रतिभूति राशि के साथ दिनांक 29.09.2025 को दोपहर 2.10 बजे तक निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
बोली (Bid) खोलने का समय	दिनांक 29.09.2025 को सांय 4.00 बजे

निदेशक
(SSAAT)

राजस्थान-सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक एफ 61(102)/SSAAT/संस्था/बिड पत्रावली/2020/

दिनांक

06 मैन विद मशीन तकनीकी बिड- प्रपत्र
(तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करें)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी,(SSAAT) जयपुर में 06 मैन विद मशीन के लिए तकनीकी बिड प्रपत्र :-

1.बोलीदाता /संवेदक का विवरण

- i. नाम.....
- ii. पता
- iii. टेलीफोन न./मोबाईल न.....
- iv. ई: मेल पता

2.बिड शुल्क जमा कराने का विवरण:-

राशि रुपये 500/- डी0डी0/बैंकर चैक सं0..... दिनांक.....बैंक का नाम.....

3.बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने का विवरण:-

राशि रुपये 19600/- डी0डी0/बैंकर चैक सं0.....दिनांक..बैंक का नाम.....

4.रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण :-

क्र.सं	विवरण	रजिस्ट्रेशन नं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट :- 1. नियमानुसार जो भी लागू है उनमें सम्पूर्ण सूचनायें अंकित करें तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। यदि फर्म पर कोई बिंदु लागू नहीं है, तो पचास रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर लागू नहीं होने के कारणों सहित सत्यापन करें।

5. कार्य का अनुभव का विवरण:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	कार्य की अवधि

नोट – फर्म को विगत पाच वर्षों में न्यूनतम तीन कार्यालयों में मैन पावर आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार विवरण देवे एवं संतोषजनक कार्य पूर्ण की प्रति संलग्न करे।

6. बोली दाता/संवेदक के बैंक की डिटेल्:-

बैंक का नाम मय ब्रान्च.....

खाता न.....

खाते का प्रकार.....

IFSC CODE.....

मैंने/हमने सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी,(SSAAT)जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या दिनांक में वर्णित एवं बिड प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैंने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मैं/हम मानने के लिए बाध्य हूँ/हैं।

दिनांक

बोलीदाता/ संवेदक के हस्ताक्षर
(मय सील)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा की जानी वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो सोसायटी प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त बिड को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी,(SSAAT) जयपुर को प्रदत्त करता हूँ/करते है।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
(मय सील)

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

.....

.....

मो0 न0.....

ई-मेल आईडी.....

राजस्थान-सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

(वित्तीय बिड में प्रस्तुत करें)
मैन विद मशीन के लिए वित्तीय बिड

1. संवेदक का नाम, पता, मय मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी.
2. GSTIN No.:
3. PAN No.:
4. EPF No. :
5. ESI No. :
6. प्रस्तुत की जाने वाली दर :-

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	उपकरण किराया प्रति माह प्रति ईकाई	EPF दर प्रतिशत (नियोक्ता) (कॉलम 5 पर) 13 प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत (नियोक्ता) (कॉलम 5 पर) 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि प्रति माह प्रति ईकाई	कुल राशि प्रतिमाह प्रति ईकाई (कॉलम 5+6+7+8+9=10)	कोई भी कर या अन्य राशि की मांग हो तो अंकित करें।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं यू.पी.एस मय प्रशिक्षित कार्मिक उच्च कुशल	06 (छः)	9334 /— प्रतिमाह							

1. न्यूनतम दर दाता (एल 1) का निर्धारण कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8 एवं 9 के योग जो कॉलम 10 में दर्शाया गया है के आधार पर होगा।
2. आपूर्ति किये जाने वाले कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू.पी.एस. मय प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में विभाग की आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
3. संवेदक को कॉलम संख्या 10 में अंकित दरों पर भुगतान किया जायेगा एवं वस्तु एवं सेवा कर की राशि यदि लागू हो तो नियमानुसार अतिरिक्त रूप से देय होगी यदि संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कर (जी.एस.टी. आदि) अतिरिक्त लिया जाता है, तो वह स्पष्ट रूप से कॉलम संख्या 11 में अंकित करेगा। इसके अभाव कॉलम 10 में वर्णित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।
4. यदि किसी संवेदक पर कोई कर देयता नहीं बनती है तो वे कॉलम संख्या 11 में "कोई कर देय नहीं" अंकित करेंगे।
5. संवेदक को न्यूनतम सर्विस चार्ज 1 रु से कम प्रस्तुत करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
(मय सील)

निविदा शर्तें

निविदा की शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के यथा संशोधित समस्त प्रावधान लागू होंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित बोलादाता/संवेदक का होगा।
3. वित्त G&T विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(1) वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 एवं 14.11.2018 एवं समय पर जारी अन्य परिपत्र/आदेश आदि में समस्त शर्तें लागू होंगी।
4. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
5. संवेदक/सेवा प्रदाता फर्म द्वारा कार्यालय में आदेश के अनुसार तुरन्त उपकरण व प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध कराने होंगे।
6. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिले के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल भुगतान किया जायेगा।
7. मशीने प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से सांयकाल 6.00 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवश्यकता होने पर कार्यालय समय के बाद इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
8. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जाएगा तत्पश्चात सोसायटी द्वारा वहन किया जाएगा।
9. विभाग द्वारा केवल स्थान एवं बिजली फिटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी। उपकरणों के रखरखाव की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
10. कम्प्यूटर नियमित रूप से कार्यरत रखने का दायित्व फर्म का होगा। कम्प्यूटर की खराबी अथवा ऑपरेटर की अनुपस्थिति के कारण सोसायटी को आवश्यक कार्य कराने के लिए फर्म द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, यदि फर्म द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा 500 रु. प्रति इकाई प्रतिदिन शास्ती के रूप में कटौती फर्म के भुगतान में से की जायेगी।
11. यदि कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे तो कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि का भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा।

12. निविदा समाप्ति के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से निविदा अवधि को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
13. सभी उपकरण नीचे अंकित स्तर के अनुरूप होंगे एवं स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं। कम्प्यूटर स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार होगा:—

Computer- Intel Core i5/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4 GB or higher, Hard disk 01 TB or more, 21" Monitor/LED or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software License will be borne by the contractor.

Printer - Black and white laser Multifunction printer with scanner with speed 20 ppm or more. For specific needs, Dot Ma-trix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

UPS- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

14. कार्मिक जो उपलब्ध कराये जायेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार की होगी :-

1. स्नातक पास, हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान, मंगल फॉन्ट में टाईप का ज्ञान, ई-मेल व इंटरनेट का ज्ञान होना अनिवार्य है।
15. कम्प्यूटर सिस्टम को सही रखने एवं उपयुक्त योग्यता के अनुसार ऑपरेटर रखने की पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। यदि विभाग की संतुष्टि से कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक करने हेतु कहा जाएगा यदि निर्धारित अवधि में ठीक नहीं करता है तो निविदादाता को 15 दिवस का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकती है।
16. सभी उपकरणों की चोरी या अन्य नुकसान संवेदक का होगा वह चाहे तो इन उपकरणों का स्वयं के खर्च पर बीमा करा सकता है।
17. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं भुगतान मासिक तौर पर संतोष जनक कार्य के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में पूर्व माह की देय जमा कराई गई राशि के विवरण एवं EPF व ESI राशि जमा के चालान की प्रति सहित विधिवत सक्षम अनुमोदन उपरान्त चैक/डीडी/ऑनलाईन तरीके द्वारा किया जायेगा।
18. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता को होगा।
19. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि के अतिरिक्त रुप से देय होगा। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन कर उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/उपनियमों अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
21. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

22. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने/कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छटनी मुआवजा आदि देने की समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता को होगा।
24. संवेदक/बोलदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या भाडे पर (Sub-Let) नहीं देगा।
25. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को सूचित किया जायेगा। और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
26. दर संविदा के अधीन कीमते कीमत गिरने के खण्ड के अध्यक्षीन होगी/कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा किया विधि है को यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
27. सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले प्रशिक्षित ऑपरेटर की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करनी होगी :-

क्र. सं.	प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	इ.पी.एफ, पंजीकरण संख्या दिनांक	ई.एस.आई, पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	शैक्षणिक योग्यता
----------	------------------------------------	-----------------	-----------	--------------------------------	------------------------------------	------------------

28. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 07 दिवस में प्रारूप 17 में रु. 500/- नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(1)वित्त/G&T/SPFC/2017 दिनांक 18.12.2020 के अनुसार कार्यादेश राशि के 05 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी व जमा कराई गई अमानत राशि का समायोजन कर दिया जायेगा।

(ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

29. बिड प्रक्रिया किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
30. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर

(मय सील)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Director SSAAT Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Secretary Rural Development Jaipur**

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. 213 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable. (b) The fee shall be paid in the form

of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address: 214 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

2. Name and address of the respondent(s): (i) (ii) (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:.....

.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected; 215 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of 216 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.